

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3927
उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

दिव्यांगजन

3927. श्री हैबी ईडन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि केरल में यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए केवल 11 नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिससे दिव्यांगजन को यह सुविधा प्राप्त करने में काफी देरी हो रही है;
- (ख) क्या सरकार सभी जिलों में अधिक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भर्ती के लिए केरल सामाजिक न्याय विभाग को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;
- (ग) क्या सरकार को पता है कि केरल में विशेष स्कूलों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के फंड पिछले चार से पांच वर्षों से लंबित हैं;
- (घ) क्या सरकार ने इस बकाया राशि को चुकाने और भविष्य में समय पर धन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार चिकित्सा पेशेवरों की नियुक्ति करने हेतु नोडल प्राधिकारी हैं। विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), भारत सरकार के सहयोग से 12.03.2024 को संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। चिकित्सा पेशेवरों की कमी को पूरा करने तथा देश भर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए, चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड में निजी चिकित्सक/डॉक्टर को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तथा उस बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी डॉक्टर होगा।

(ख): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग), (घ) और (ङ): विभाग दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जारी करता है। केरल में डीडीआरएस के अंतर्गत परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को चालू वित्त वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में जारी सहायता अनुदान (जीआईए) का विवरण नीचे दिया गया है-

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (20.03.2025 की स्थिति के अनुसार)
अनुदान (करोड़ रुपए में)	6.28	7.25	7.62	4.55	16.61

विभाग केरल राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को नियमित रूप से अनुदान जारी करता आ रहा है।
